बाइडन पर यूक्रेन की कंपनी से 50 लाख डॉलर रिश्वत लेने का आरोप

फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, राष्ट्रपति बाइडन को रिश्वत के रूप में यूक्रेनी गैस कंपनी बरिस्मा होल्डिंग्स ने यह रकम दी थी

वॉशिंगटन, 10 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एक बड़े संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। बाइडन पर यूक्रेन की एक कंपनी से 5 मिलियन (50 लाख) डॉलर की रिश्वत लेने का आरोप है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति बाइडन को रिश्वत के रूप में यूक्रेनी गैस कंपनी बरिस्मा होल्डिंग्स के एक कार्यकारी अधिकारी से 5 मिलियन डॉलर का भुगतान मिला था। बता दें कि ये वही कंपनी है जहां जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन बोर्ड सदस्य थे। हंटर बाइडन ने इस कंपनी में लंबे समय तक काम किया था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस गैस फर्म के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है। यूक्रेनी वकील विक्टर शॉकिन इसकी जांच कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे उस कार्यकारी अधिकारी ने जो बाइडन से फेवर मांगा था क्योंकि कंपनी आरोपों के कारण निवेश करने में असमर्थ थी। खबर के मुताबिक, 'भ्रष्टाचार की जांच को समाप्त करने के लिए जो बाइडन को 50 लाख डॉलर का भुगतान किया गया था। एफ.बी.आई. को इसके बारे में जून 2020 में एक गोपनीय सोर्स से पता चला था। सोर्स ने संकेत दिया था कि जो बाइडन और एक विदेशी व्यक्ति कथित रूप से एक आपराधिक रिश्वत कांड में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट में एक एफ.बी.आई.- एफ.डी. 1023 फॉर्म का जिक्र किया गया है, जिसका इस्तेमाल एफ.बी.आई. एजेंटों द्वारा गोपनीय सूत्रों द्वारा प्रदान की गई असत्यापित जानकारी को दर्ज करने के लिए किया जाता है। एफ.बी.आई. के फॉर्म में इंटरव्यू किए गए सोर्स का जिक्र है जिसे "अत्यधिक विश्वसनीय" बताया गया है।

- रिपोर्ट के अनुसार, उक्त गैस फर्म के कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ इस मामले में जांच चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे उस कार्यकारी अधिकारी ने राष्ट्रपति बाइडन से फेवर मांगा था, क्योंकि कंपनी आरोपों के कारण निवेश करने में असमर्थ थी।
- खबर के मुताबिक, इस गैस कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को बंद करने के लिए बाइडन को 50 लाख डॉलर का भुगतान किया गया था।

रिपोर्टों के मुताबिक, उस एफ.बी.आई. दस्तावेज में कथित तौर पर सारी जानकारी लिखी हुई है कि कैसे एक यूक्रेनी वकील को हटाने के लिए जो बाइडन को 50 लाख डॉलर दिए गए थे। वह पैसा कथित रूप से यूक्रेनी तेल कंपनी बरिस्मा होल्डिंग्स के मालिक की तरफ से ही आया था। इस बीच रिपब्लिकन सांसदों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति बाइडन के अलावा, उनके बेटे हंटर बाइडन ने भी यूक्रेनी गैस कंपनी को भ्रष्टाचार की जांच से बचाने के लिए 50 लाख डॉलर हासिल किए हैं। सोर्स ने बताया कि 2015 से कई वर्षों में बरिस्मा के एक वरिष्ठ कार्यकारी के साथ उसकी कई बैठकों पर चर्चा हुई।

पूर्व प्र.मंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसद पद से दिया इस्तीफा

लंदन, 10 जून (वार्ता) ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टोरी सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन ने एक संसदीय समिति के एक बयान के बाद यह कदम उठाया। उन्हें पार्टीगेट मामले को लेकर संसद से जबरन बाहर किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री ने कॉमन्स (संसद के निचले सदन) विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट को पहले ही देख लिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन का उल्लंघन कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट (प्रधानमंत्री आवास) में पार्टियां आयोजित करने के मुद्दे पर संसद को भ्रमित करने के मामले में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जॉनसन इस मामले में एक संसदीय समिति की जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट पार्टियों का आयोजन कर निचले सदन को गुमराह किया था। जॉनसन ने एक विस्फोटक और लंबे बयान में समिति को 'कंगारू कोर्ट' कहा था।

मुसलमानों को ओ.बी.सी. कोटे के तहत आरक्षण जायज?

नई दिल्ली, 10 जून (वार्ता)। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल में आबादी के अनुपात से कहीं अधिक तमाम मुस्लिम समुदायों को बिना प्रक्रिया को अपनाये पिछड़ी जातियों की सूची में जगह देने पर हैरानी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल की 70.5 प्रतिशत आबादी हिन्दू और करीब 27 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है। लेकिन पिछड़े वर्ग की सूची में दर्ज 179 जातियों में से 118 जातियां मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के पहले राज्य में 108 जातियां इस श्रेणी में सूचीबद्ध थीं जिनमें से 53 मुस्लिम एवं 55 हिन्दू जातियां शामिल थीं लेकिन वर्ष 2011 के बाद 71 और जातियां इस सूची में जोड़ी गयीं जिनमें से 65 मुस्लिम एवं केवल छह हिन्दू जातियां शामिल थीं।

उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल सरकार के सांस्कृतिक शोध संस्थान (सी.आर.आई.) ने अध्ययन करके इन जातियों को ओ.बी.सी. की सूची में जोड़ने की सिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस स्तर पर जा कर मुस्लिम समुदायों को ओ.बी.सी. की श्रेणी प्रदान करने के पीछे वोट बैंक की राजनीति दिखायी देती है। अहीर ने कहा कि पिछड़े वर्ग की आबादी में 34 प्रतिशत हिन्दू और 65.9 प्रतिशत मुस्लिम हैं। राज्य में ओ.बी.सी. की दो श्रेणियां हैं- श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए को दस प्रतिशत एवं श्रेणी बी को सात प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। श्रेणी ए में कुल 81 जातियां (8 हिन्दू एवं 73 मुस्लिम) और श्रेणी बी में 98 जातियां (53 हिन्दू एवं 45 मुस्लिम) हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय कुल 45 प्रतिशत आरक्षण लागू हैं जिनमें से 17 प्रतिशत ओ.बी.सी. के लिए और बाकी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा के हिसाब से ओ.बी.सी. को 22 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बारे में पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को लिखा है लेकिन वे चुप्पी साधे हुए हैं।

- राष्ट्रीय ओ.बी.सी. आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया
- राष्ट्रीय ओ.बी.सी. आयोग का मानना है कि प. बंगाल सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में किसी भी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

अहीर ने कहा कि केरल एवं तेलंगाना में भी इसी प्रकार की विसंगतियों की शिकायतें मिलीं हैं। जिनकी जांच करायी जा रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि बात मुस्लिम या हिन्दू की नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर बने कानून के मुताबिक मुस्लिम पिछड़े वर्गों को भी इसका फायदा मिलता है लेकिन जातियों के निर्धारण का तरीका न्याय सम्मत नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया तो वैसे ही मान लिया गया।

काफी समानताए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए कर्नाटक चुनाव में मुफ्त उपहारों का वादा किया गया, विशेषकर महिला मतदाताओं को लक्षित करके, जिससे कांग्रेस को जीत में मदद मिली।

मध्य प्रदेश में भाजपा बचाव की मुद्रा में दिखी क्योंकि मुख्यमंत्री चौहान और अन्य पार्टी नेताओं के बीच आंतरिक कलह है जिनमें शामिल है राज्य भाजपा अध्यक्ष वी.डी.शर्मा, नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके मुकाबले कांग्रेस में अंतर्कलह कम है, जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खेमों तक सीमित है।कर्नाटक में नुकसान के बाद भाजपा नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे ताकि वे मध्य प्रदेश नहीं हारें, जो 2005 से पार्टी का गढ़ रहा है। बीच में कुछ समय कमनलाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आने के अलावा चौहान ही मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ये कयास है कि पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री के लिए नए चेहरे को आगे कर सकता है ताकि चौहान के विरूद्ध एंटी इंकबैंसी का तोड़ निकल सके।

बांग्लादेश में एक भारतीय 11 करोड़ की कोकीन के साथ गिरफ्तार

ढाका, 10 जून (वार्ता)। बंगलादेश की राजधानी ढाका के शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक को एक किलो 800 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है।

सीमा शुल्क खुफिया एवं जांच निदेशालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। निदेशालय ने बताया कि बरामद कोकीन की कीमत करीब 11 करोड़ रुपये है।

- बंगलादेश में एक भारतीय नागरिक को एक किलो 800 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है।

एन.सी.पी. प्रमुख ने अजित पवार के पर कतरे

- शरद पवार ने पार्टी के दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाये, पुत्री सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया
- माना जा रहा है कि, इस फैसले से शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। यह इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है कि बीते दिनों अजित पवार कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी बगावती चाल दिखा चुके हैं।

मुंबई, 10 जून। एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी छाप लंबे समय तक बनी रह सकती है। पवार ने शनिवार को सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। पवार ने अप्रत्याशित तौर पर दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एन.सी.पी. की राजनीति को एकदम नये मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि, इस फैसले से शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। यह इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है कि बीते दिनों अजित पवार कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर अपनी बगावती चाल दिखा चुके हैं। ऐसे में एन.सी.पी. अध्यक्ष के फैसले को बड़े पॉलिटिकल कैनवस पर देखा जा रहा है। नजर इस बात पर जा टिकी है कि शरद पवार के इस फैसले के बाद अजित पवार और उनके समर्थकों का रुख क्या होगा।

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एन.सी.पी. चीफ का यह ताजा फैसला बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री दिलाने की कोशिश है। पार्टी लाइन में यह पहले ही साफ हो चुका था कि, भतीजे अजित पवार का दायरा महाराष्ट्र की राजनीति तक ही सीमित रहेगा। बीते काफी समय से अजित को इस भूमिका में देखा भी गया है। अब सुले और पटेल के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अजित के सीमित राजनीतिक दायरे पर मुहर लगती दिख रही है। ऐसी स्थिति में इस बात का भी खतरा है कि अजित पवार का खेमा पार्टी आलाकमान से नाराज हो सकता है। मगर, यह भी देखने वाली बात होगी कि यह नाराजगी किस हद तक आगे बढ़ती है। हालांकि, फिलहाल अजित पवार की नाराजगी सामने नहीं आई है। एन.सी.पी. जनरल सेक्रेटरी सुनील तटकरे ने कहा कि अजित दादा ने हमेशा संगठन के लिए काम किया है। उन्होंने बीते 24 वर्षों से पार्टी को मजबूत करने में योगदान दिया है। पार्टी के काम और जिम्मेदारियां निभाने के लिए किसी पद की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि अजित पवार परेशान नहीं हैं, वह महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इस मामले पर एन.सी.पी. नेता छगन भुजबल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही चुनाव का काम और लोकसभा-राज्यसभा का काम बांट दिया जाएगा। चुनाव नजदीक आता देख उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अहम ऐलान है।

एन.सी.पी. में शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा? यह सवाल लंबे समय से उठाया जाता रहा है। इसके जवाब में अजित पवार को गद्दी मिलने के कयास लगते थे। हालांकि, अजित के बगावती तेवर ने कई बार इस पर प्रश्नचिह्न भी खड़े कर दिए। माना जा रहा था कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी एन.सी.पी. के भीतर अजित पवार के कंधे पर है। अगर कल को सी.एम. बनने का मौका मिला तो अजित पवार का नाम सबसे आगे होगा। मगर, शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बड़ा राजनीतिक खेल कर दिया है। बहस अब अजित पवार की तरफ से मोड़ दी गई है और इस मामले में उन्हें करीने से किनारे लगाने का प्रयास दिखता है। यहां सवाल खड़ा होता है कि अजित पवार को शरद पवार अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन रहे हैं तो आगे का उनका प्लान क्या है? क्या शरद की जगह सुप्रिया सुले ले सकती हैं? अगर हां तो फिर उन्होंने 2 कार्यकारी अध्यक्ष क्यों चुने? दरअसल, बीते दिनों शरद पवार ने जो इस्तीफे वाला दाव चला उससे कई चीजें साफ हो गईं।

सड़क दुर्घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मौके पर बीमा कंपनी के अधिकारी राकेश सोलंकी व पैनल अधिवक्ता सूरज व्यास और अधिवक्ता किशन सोनी व संजय ओझा उपस्थित थे।

राजेश पायलट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पायलट की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी की चर्चाओं और अटकलों में कितना दम था। मंत्री मुरारी लाल मीणा एवं विधायक गजराज खटाना कार्यक्रम की तैयारियों को व्यवस्थित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान गुर्जर छात्रावास में स्व. राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा।

'अपराधिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनीता जैन की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस दिया।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि पारिवारिक रंजिश के चलते याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके परिवारजनों ने बनीपार्क थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने पावर ऑफ अटॉर्नी में फजीवाड़ा किया। रिपोर्ट पर अनुसंधान अधिकारी ने उचित अनुसंधान किए बिना ही याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को कई माह तक जेल में रहना पड़ा। वहीं मामले में याचिकाकर्ता को कोर्ट ने दोषमुक्त भी कर दिया। एफ.एस.एल. जांच में भी सामने आया कि पावर ऑफ अटॉर्नी में हस्ताक्षर फर्जी नहीं थे। याचिका में कहा गया कि अदालत से बरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई में जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद अनुसंधान अधिकारी को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ 17 सी.सी.ए .के तहत कार्रवाई की गई। याचिका में गुहार की गई है कि प्रकरण में जांच के लिए कमेटी गठित की जाए और उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उनके मूलभूत अधिकारों के हनन के मुआवजे के तौर पर पचास-पचास लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिलाए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

'देश का वर्तमान राजनीतिक माहौल 1977 जैसा है'

मुम्बई, 10 जून (वार्ता)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने देश के वर्तमान राजनीतिक माहौल की तुलना 1977 से करते हुए शनिवार को विश्वास जताया कि इस बार विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देश में परिवर्तन आयेगा।

पवार ने राकांपा के 25वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर अपने संदेश में कहा, मुझे याद है कि 1977 में देश में ऐसी ही स्थिति थी। कोई एक नेता सामने नहीं था, लोगों ने बदलाव का मन बना लिया, चुनाव के वक्त देश में एक नया माहौल पैदा हो गया और जनता पार्टी की हुकूमत आयी थी।

उन्होंने विपक्ष की एकता पर बल देते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में अलग-अलग विचारधारा की पार्टियों को एक साझा कार्यक्रम पर आगे चलने की तैयारी रखकर हाथ मिलाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि इस देश की जनता परिवर्तन के लिए इन सभी की मदद करेगी। पवार ने बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल के नेता नीतीश कुमार की मेजबानी में 23 जून को पटना में होने वाली बैठक का उल्लेख किया।

- शरद पवार ने यह टिप्पणी करते हुये कहा कि, 1977 की भांति विपक्ष एक बार फिर एकजुट होगा।

अगर ट्रम्प दोषी पाये गये तो, वोट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जी.ओ.पी. उम्मीदवार खुलकर ट्रम्प की आलोचना कर रहे हैं। अर्कंसास के पूर्व गवर्नर असा हचिंसन ने अभियोग के बाद एक बयान जारी कर कहा है कि ट्रम्प ध्यान बंटा रहे हैं और उन्हें अपना अभियान बंद कर देना चाहिए।

यह सब होने से पहले ट्रम्प के पूर्व उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने अपने पूर्व अधिकारी के लिए कहा, "जो कोई स्वयं को संविधान से ऊपर रखता है उसे कभी, "संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए।"

शायद ट्रम्प के सबसे कटु आलोचक है न्यूजर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी। उन्होंने न्यू हैम्पशायर में एक उद्घाटन समारोह में कहा कि "ट्रम्प को आईने की सनक है" और "वे कभी गलती स्वीकार नहीं करते।" बल्कि जो कुछ गलत होता है उसका दोष डालने के लिए किसी और को ढूंढ लेते हैं जबकि जो सही हो रहा है उसका श्रेय स्वयं लेते हैं। लेकिन ट्रम्प विरोधी ये आवाजें कमजोर हैं। हचिंसन, क्रिस्टी और पेंस गुरूवार रात को शांत रहे और अधिकांश लोगों ने ट्रम्प की बजाय न्याय विभाग की आलोचना की। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस, साउथ कैरोलिना के सीनेटर टिम स्कॉट और कई रिपब्लिकन कांग्रेसियों ने दावा किया था कि न्याय विभाग को ट्रम्प के विरूद्ध तैयार किया गया है और उन्होंने दोहरे मापदंड की शिकायत की।

डीसैंटिस ने ट्वीट कर कहा, "संघीय कानून प्रवर्तन को ज्यादा अधिकार देने का अर्थ है। खुले सामाजिक जीवन के लिए खतरा। हमने वर्षों तक कानून को असंतुलित रूप से लागू होते देखा है जो राजनैतिक झुकाव पर निर्भर करता है। ट्रम्प के पीछे इतने जोर-शोर से क्यों पड़े हैं जब हिलेरी (क्लिंटन) या हंटर (बाइडन) के मामले में शांत है। डीसेंटिस प्रशासन न्याय विभाग को जिम्मेवार बनाएगा, राजनैतिक पक्षपात समाप्त करेगा और सशस्त्रीकरण को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तकनीकी व्यवसायी विवेक रामास्वामी, जो स्वयं दौड़ में शामिल है, ने यहां तक कहा है कि वे राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन ट्रम्प को क्षमा कर देंगे। यह 2024 का चुनाव विचित्र और उल्लेखनीय होता जा रहा है। एक उम्मीदवार भूतपूर्व राष्ट्रपति है जिस पर दोहरा अभियोग चल रहा है, सुनवाई महीनों चल रहा है और न्यूयॉर्क में एक पेशी अगले साल है।

और ट्रम्प को केवल इन संभावित परिवर्तनों का ही सामना नहीं करना है। ट्रम्प की एक योजना पर एक मुकदमा जॉर्जिया में भी है, जिसमें चुनाव के नतीजे बदलने का आरोप है और एक अपराधिक मकुदमा 6 जनवरी को कैपीटॉल में हुए दंगों के संबंध में है।

यदि ट्रम्प को सजा होती है और जेल भेजा जाता है तो भी वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं हालांकि सजायाफ्ता होने पर वे फ्लोरिडा में वोट नहीं दे पाएंगे। यह देश के लिए विचित्र स्थिति है, चाहे यह न भी देखे कि ट्रम्प और बाइडन दोनों अमेरिका में सबसे पुराने चुनाव प्रत्याशी हैं और दोनों अलोकप्रिय हैं।

भारतीय ड्राइवरों के लिये भारी मार्केट ...

वाहन चला सकते हैं और जिनके पास वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसैंस हैं। इस पद के लिए अच्छे, कुशल ड्राइवर का होना आवश्यक है। मगर इसकी शर्त यह है कि उसे अंग्रेजी आनी चाहिए, जिसके कारण अन्य तरीकों से योग्य अधिकांश ड्राइवर अयोग्य हो जाते हैं। हालांकि इस काम के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है मगर अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि उस देश में यह आवश्यक है।

इस समय बंगलुरू स्थित कर्नाटक सरकार के इंटरनैशनल माइग्रेशन सैंटर में यूरोप के दो देशों पोलैंड और हंगरी के लिए बस ड्राइवरों की भर्ती हो रही है। कर्नाटक सरकार के कौशल उद्यमिता विकास अनुभाग को हंगरी से ट्रक डाइवरों और पोलैंड से बस ड्राइवरों की डिमांड मिल सकती है।

इंटरनैशनल माइग्रेशन सैंटर कर्नाटक विदेशों में रोजगार के लिए अधिकृत सूचना, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और भर्ती की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

केवल ड्राइवर नहीं बल्कि भारतीय इन बढ़ती उम्र वाली आबादी के देशों को चलाएंगे, चाहे शहरों का रख-रखाव हो या आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाना। यह बात हैदराबाद स्थित श्रम विशेषज्ञ एम. भारत भूषण ने कही।

भारत भूषण, जिन्होंने देश के युवाओं की रोजगार चुनौतियों और अवसरों पर विस्तृत शोध किया है, ने कहा कि यह अवसर का एक ऐसा द्वारा है जिसका विभिन्न सरकारों और केन्द्र द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि भारत अपनी आबादी के संसाधन का पूरा उपयोग कर सके।

- पर, सख्त शर्त यह है कि, इन भारतीय ड्राइवरों को अंग्रेजी जरूर आनी चाहिए।

भारत भूषण ने कहा, "दुनिया की आबादी की उम्र बढ़ रही है इसका अर्थ है कि हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए क्योंकि हमारे पास कुशल और अर्द्धकुशल कामगारों की फौज है जो अवसर का इंतजार कर रही है।

कर्नाटक के केन्द्र को अपने नवाचार के लिए बधाई देते हुए भारत भूषण ने कहा कि यह स्पष्ट मामला है देश में हर सरकार के लिए दुनिया में कुशल कामगार निर्यात करने का। यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल क्योंकि किसी को विदेशों की जिम्मेवारी लेनी होगी और भारत सरकार को ठोस योजना बनाना होगी जिससे देश के युवाओं की कई समस्याएं आसान हो जाएं। कर्नाटक से ड्राइवर्स यूरोप भेजने के लिए केन्द्र येलागांका के ड्राइविंग ट्रैक्स पर ड्राइवरों के टैस्ट ले रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हें 60,000 रूपये प्रति माह भत्ता मिलेगा और नौकरी लगने पर 1 से 5 लाख रूपये प्रति माह वेतन मिलेगा। भारत ने कहा, "हमें अब तक व्यापारिक शोध कर उन देशों की पहचान कर लेनी चाहिए जहां श्रमिकों की कमी है और वहां भारतीय कुशल कामगारों को भेजना चाहिए।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908